औद्योगिक आपूर्ति प्राइवेट लिमिटेड एवं अन्य

बनाम

भारत संघ एवं अन्य

7-8-1980

(वी.और. कृष्णा अय्यर, ओ. चिन्नप्पा रेड्डी और एपी सेन, न्याधिपतिगण)

क्या कोयला खदान का ठेकेदार उपधारा के तहत मालिक है।(1) कोकिंग कोल माइंस (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम,1972 (इसके बाद राष्ट्रीयकरण अधिनियम के रूप मेंसंदर्भित) की धारा 4 का और यदि हां, तो क्या ऐसे ठेकेदार द्वारा स्थापित या लाई गई मशीनरी, संयंत्र, उपकरण और अन्य संपत्तियों जैसी अचल संपत्तियां केंद्र सरकार में निहित हैं। वे एक सहायक प्रश्न को भी जन्म देते हैं, अर्थात्, क्या कोयला खान (संरक्षण, सुरक्षा और विकास) अधिनियम, 1952 की धारा4 के तहत स्थापित पूर्ववर्ती कोयला बोर्ड से निर्दिष्ट तिथि तक सब्सिडी, संरक्षण नामक निधि से प्राप्त की जा सकती है और सुरक्षा निधि, नियत दिन से पहले ऐसे जुटाने वाले ठेकेदार द्वारा, उप-धारा के तहत उनकी शक्तियों के आधार पर केंद्र सरकार द्वारा प्राप्त की जा सकती है। (3) राष्ट्रीयकरण अधिनियम की धारा 22, ऐसे ठेकेदार सहित अन्य सभी व्यक्तियों को बाहर करने के लिए और उप-धाराओं के तहत लागू किया गया। (4) एस. 22 कोकिंग कोयला खदान की देनदारियों के निर्वहन के लिए, जिसे नियत दिन तक चुकाया नहीं जा

सका। उक्त समझौते के तहत, याचिकाकर्ताओं को 20 साल की अवधि के लिए कच्छी बलिहारी कोलियरी के प्रबंध ठेकेदार के रूप में नियुक्त किया गया था। सीएल के तहत.7 (ए) याचिकाकर्ताओं को अपनी लागत पर उपकरण, मशीनरी और संयंत्र जैसी अचल संपत्ति स्थापित करने और उक्त कोलियरी में स्टोर जैसी मौजूदा संपत्ति के रूप में निवेश करने और ठेकेदारों को बढ़ाने के समान काम करने की आवश्यकता थी। सीएल द्वारा. 7 (बी) इस प्रकार स्थापित की गई अतिरिक्त मशीनरी और याचिकाकर्ताओं द्वारा लाए गए सामान और बर्तन पूरी तरह से याचिकाकर्ताओं की संपत्ति बने रहेंगे और समझौते के निर्धारण पर वे सीएल के प्रावधानों के अधीन हकदार थे। 17 अक्टूबर, 1971 को राष्ट्रपति ने 214 कोकिंग कोयला खदानों और 12 कोक ओवन संयंत्रों के प्रबंधन को जनहित में केंद्र सरकार द्वारा अपने अधिकार में लेने का प्रावधान करने के लिए कोकिंग कोयला खदान (आपातकालीन प्रावधान) अध्यादेश 1971 प्रख्यापित किया। याचिकाकर्ताओं ने दिल्ली उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका दायर कर यह घोषणा करने की मांग की कि उपधारा धारा 4 का (1) याचिकाकर्ताओं के अधिकार, शीर्षक और हित के अधिग्रहण का प्रावधान नहीं करता है, क्योंकि ठेकेदारों को पालने के कारण वे राष्ट्रीयकरण अधिनियम की धारा 3 (एन) के अर्थ के तहत मालिक नहीं थे और इसलिए, वे दो खदानों में स्थापित मशीनरी, संयंत्र और उपकरण जैसी अचल संपत्तियों को नष्ट करने और हटाने के हकदार थे और साथ ही फर्नीचर, स्टोर आदि जैसी चल और वर्तमान

संपत्तियों को हटाने के भी हकदार थे और आगे सब्सिडी की राशि वसूलने के भी हकदार थे। रु. तत्कालीन कोयला बोर्ड से केंद्र सरकार द्वारा 4,50,000/- रुपये एकत्र किये गये।

उच्च न्यायालय ने याचिकाकर्ताओं के दावे को काफी हद तक अस्वीकार कर दिया, यह मानते हुए कि वे खान अधिनियम, 1952 की धारा 2 (1) के साथ पढ़े गए राष्ट्रीयकरण अधिनियम की धारा 3 (ए) में परिभाषित मालिक शब्द के अर्थ में आते हैं। हालाँकि, यह माना गया कि सब्सिडी की राशि रु। याचिकाकर्ताओं द्वारा किए गए रेत भंडारण और कठिन खनन कार्यों की लागत की प्रतिपूर्ति के रूप में कोयला बोर्ड से प्राप्त होने वाली 4,50,000/- को उप-धारा के अंतर्गत " कोकिंग कोयला खदान के कारण राशि" के रूप में नहीं माना जा सकता है। . (3) धारा 22 और, इसलिए, उप-एस के तहत केंद्र सरकार द्वारा उपयोग नहीं किया जा सका। (4) कोकिंग कोयला खदान की देनदारियों के निर्वहन के लिए धारा 22।

केवल भारत संघ द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार किया गया तथा कम्पनी की और से प्रस्तुत अपील को अस्वीकार करते हुए यह

अभिनिर्धारित किया:- गया कि अपीलार्थीगण राष्ट्रीयकरण अधिनियम की धारा 3(एन) एवं धारा 2 माईन्स अधिनियम ,1952 में प्रयुक्त शब्द " स्वामी" के दायरे में आते है। इसके अतिरिक्त उक्त शब्द का अन्य अर्थ

लगाए जाने पर विधायिका द्वारा बनायी गयी विधि के उददेश्य तथा विधायिका के मंव्य को विफल कर देता है।

संसद ने उचित विचार-विमर्श के साथ, राष्ट्रीयकरण अधिनियम को सर्वव्यापी और पूरी तरह से प्रभावी बनाने के लिए खान अधिनियम, 1952 की धारा 2 (1) में मालिक की विस्तृत परिभाषा को शामिल करके धारा 3 (एन) में अपनाया। यह परिभाषा इतनी व्यापक है कि इसमें व्यक्तियों की तीन श्रेणियां शामिल की जा सकती हैं: (i) खदान के संबंध में वह व्यक्ति जो मेरा या उसके किसी हिस्से का तत्काल मालिक या पट्टेदार या कब्जाधारी है, (ii) खदान के मामले में व्यवसाय जिसका संचालन एक परिसमापक या रिसीवर द्वारा किया जाता है, ऐसे परिसमापक या रिसीवर, और (iii) किसी कंपनी के स्वामित्व वाली खदान के मामले में, जिसका व्यवसाय एक प्रबंध एजेंट, ऐसे प्रबंध एजेंट द्वारा किया जाता है। प्रत्येक व्यक्तियों की एक अलग और अलग श्रेणी है और स्वामित्व की अवधारणा इसमें नहीं आती है। फिर महत्वपूर्ण अंतिम शब्द आते हैं: " लेकिन खदान या उसके किसी भी हिस्से के काम के लिए कोई भी ठेकेदार इस अधिनियम के अधीन होगा जैसे कि यदि वह स्वामी होता, परन्तु इसलिए नहीं कि स्वामी को किसी भी दायित्व से छूट मिल सके।" इस खंड को शामिल करने से मालिक और ठेकेदार दोनों को अधिनियम के उचित पालन के लिए समान रूप से उत्तरदायी बनाया जाता है। इस बात पर ज़ोर देने की

ज़रूरत नहीं है कि खान अधिनियम, 1952 में खानों और उनमें कार्यरत व्यक्तियों की सुरक्षा के लिए विभिन्न प्रावधान शामिल हैं। किसी खदान के मामले में, जिसका काम एक ठेकेदार द्वारा किया जा रहा है, वह मुख्य रूप से अधिनियम के प्रावधानों का अनुपालन करने के लिए जिम्मेदार है। यद्यपि किसी खदान या उसके किसी हिस्से के काम के लिए ठेकेदार मालिक नहीं है, वह अधिनियम के प्रावधानों के अधीन होगा, उसी तरह जैसे कि वह मालिक था, लेकिन मालिक को किसी भी दायित्व से मुक्त नहीं किया जाएगा।

राष्ट्रीयकरण अधिनियम का पूरा उद्देश्य और उद्देश्य कोकिंग कोयला खदानों के निजी स्वामित्व और उसमें निर्मित सभी हितों को जब्त करना है। यह उप-एस द्वारा प्रदान करता है। धारा 4 के (1) कि नियत दिन पर, पहली अनुसूची में निर्दिष्ट कोकिंग कोयला खदानों के संबंध में मालिकों के अधिकार, शीर्षक और हित पूरी तरह से केंद्र सरकार को हस्तांतरित हो जाएंगे और उनमें निहित हो जाएंगे। सभी अवलंबन. अब जब तक कि उप-एस में मालिक शब्द न हो। धारा 4 के (1) को एक विस्तारित अर्थ दिया गया है ताकि एक खदान या उसके किसी हिस्से के काम के लिए एक ठेकेदार को शामिल किया जा सके, कानून का उद्देश्य ही विफल हो जाएगा। यह माना जाना चाहिए कि संसद को सभी कोयला खदानों के काम करने के सामान्य पैटर्न, यानी ठेकेदारों को नियुक्त करने के बारे में पूरी जानकारी

थी। कोई भी अन्य निर्माण स्पष्ट रूप से बेहूदगी की ओर ले जाएगा और संसद को ऐसा परिणाम देगा जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। इसके परिणामस्वरूप ठेकेदार उप-धारा के तहत निहित होने के परिणामों से बच जायेंगे। (1) अधिनियम की धारा 4 और उन्हें खानों के काम के लिए उपयोग की जा रही अतिरिक्त मशीनरी, संयंत्रों और उपकरणों को नष्ट करने और हटाने की अनुमति दें।

राष्ट्रीयकरण अधिनियम की धारा 3(एन) में प्रयुक्त शब्द कब्जाधारी का अर्थ उसके सामान्य अर्थों में ही समझा जाना चाहिए। कानूनी अर्थ में, कब्ज़ाकर्ता वास्तविक कब्ज़ा करने वाला व्यक्ति होता है। ठेकेदारों को खड़ा करने वाले याचिकाकर्ता, 7 फरवरी 1969 के समझौते की शर्तों के तहत, कोलियरी के वास्तविक भौतिक कब्जे और आनंद के हकदार थे, और इसलिए, उसके कब्जे वाले थे। ऐसा होने पर, समझौते के तहत उनके द्वारा प्राप्त किए गए पर्याप्त अधिकारों के आधार पर, याचिकाकर्ताओं का कब्ज़ा अपने अधिकार में था, किसी और की ओर से कब्ज़ा नहीं था माईन्स के मुख्य निरीक्षक व अन्य बनाम लाला करमचन्द थापर वगैरह (1962)1 एस सी और, 09 का मामला भिन्न है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि राष्ट्रीयकरण अधिनियम मालिक और प्रबंध ठेकेदार को अलग-अलग परिभाषित करता है। अधिनियम में प्रयुक्त और परिभाषित शब्दों और अभिव्यक्तियों का क्रमशः वही अर्थ है जो उन्हें दिया गया है, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा

अपेक्षित न हो। राष्ट्रीयकरण अधिनियम की धारा 3 (i) में परिभाषित अभिव्यक्ति प्रबंध ठेकेदार की अभिव्यक्ति केवल उप-धाराओं के तहत मुआवजे के बंटवारे के उद्देश्य से आती है। (2) धारा 26 का। प्रस्तुतीकरण कि उपधारा में स्वामी शब्द का प्रयोग किया गया है।(1) राष्ट्रीयकरण अधिनियम की धारा 4 में एक प्रबंध ठेकेदार को शामिल नहीं किया गया है जो अधिनियम की योजना के विरुद्ध है। उपधारा में मालिक शब्द। अधिनियम की धारा 4 के (1) का अर्थ धारा 3 (एन) में निहित परिभाषा में दिया गया अर्थ होना चाहिए। इस तरह का औरक्षण याचिकाकर्ताओं को राष्ट्रीयकरण अधिनियम की धारा 3 (i) के तहत प्रबंध ठेकेदार की परिभाषा से बाहर नहीं करता है, क्योंकि उनके पास अभी भी खदान पर पर्याप्त नियंत्रण था। यह दलील कि वे नहीं बल्कि कोई और प्रबंध ठेकेदार था, केवल एक बाद का विचार है। याचिकाकर्ताओं को समझौते की शर्तों से बंधे होने के कारण उप-धाराओं के प्रावधानों से बचने की अनुमति नहीं दी जा सकती। (1) धारा 4 में, क्योंकि वे धारा में मालिक की परिभाषा के दायरे में आते हैं। राष्ट्रीयकरण अधिनियम की धारा 3 (एन)।

जब किसी कानूनी कल्पना को किसी क़ानून में शामिल किया जाता है, तो न्यायालय को यह सुनिश्चित करना होगा कि कल्पना किस उद्देश्य से बनाई गई है। उद्देश्य सुनिश्चित करने के बाद वैधानिक कल्पना पर पूरा प्रभाव डालना चाहिए और उसे तार्किक परिणति तक ले जाना चाहिए।

न्यायालय को उन सभी तथ्यों और परिणामों को मानना होगा जो कल्पना को प्रभावी बनाने के लिए आकस्मिक या अपरिहार्य परिणाम हैं। खान अधिनियम की धारा 2 (1) के साथ पढ़े गए राष्ट्रीयकरण अधिनियम की धारा 3 (एन) में मालिक की परिभाषा में "मानो वह थे" शब्दों का कानूनी प्रभाव यह है कि हालांकि याचिकाकर्ता मालिक नहीं थे, खदान के कामकाज के लिए ठेकेदार होने के नाते उनके साथ वैसा ही व्यवहार किया जाना चाहिए था, हालांकि वास्तव में, वे ऐसे नहीं थे। **ईस्ट एंड डवेलिंग कंपनी लिमिटेड** बनाम फिन्सबरी बरो काउंसिल 1952 एसी,109 पेज 132 एक कानूनी कल्पना के कानूनी प्रभाव को इन शब्दों में सामने लाता है। सब्सिडी के बिल भंडारण और संबंधित सुरक्षा कार्यों और कठिन खनन कार्यों की लागत के लिए थे, जिसे याचिकाकर्ताओं ने 17 अक्टूबर, 1971 से पहले ही अपनी लागत पर पूरा कर लिया था। बाहर। यदि ऐसा है, तो अपरिहार्य निष्कर्ष यह है कि प्रश्न में सब्सिडी की राशि नियत दिन से पहले कोकिंग कोयला खदान के कारण किसी अन्य राशि की तरह थी, और इसलिए, धारा 22 की उपधारा 3 के दायरे से बाहर नहीं आती थी।

प्रश्नगत भुगतान कोयला खदानों के भंडारण और अन्य सुरक्षा कार्यों और संरक्षण के लिए तत्कालीन कोयला बोर्ड से प्राप्त होने वाली सहायता के माध्यम से नहीं था। वर्तमान मामले में, याचिकाकर्ताओं ने स्वयं यह दिखाते हुए पहले ही रेत भंडारण और कठिन खनन कार्य किए थे और

प्रतिपूर्ति के माध्यम से सब्सिडी के लिए आवेदन किया था। रुपये का भुगतान. इसलिए, 4,50,000/- पहले से किए गए व्यय की प्रतिपूर्ति के लिए था। निस्संदेह, विवादग्रस्त राशि प्रतिपूर्ति के माध्यम से देय थी। इसलिए, याचिकाकर्ता अपनी इच्छानुसार किसी भी तरीके से धन का उपयोग करने के लिए स्वतंत्र थे। दूसरे शब्दों में,अनुदान किसी विशेष उद्देश्य या उद्देश्य से प्रभावित नहीं था।

भले ही पूर्ववर्ती कोयला बोर्ड से प्राप्त होने वाली सब्सिडी सहायता के रूप में थी, रुपये की राशि। 4,50,000/- केंद्र सरकार द्वारा वसूली योग्य थी जिसमें कोकिंग कोयला खदानें उप-धाराओं के तहत निहित हैं। (1) राष्ट्रीयकरण अधिनियम की धारा 4 और याचिकाकर्ताओं द्वारा नहीं। हालाँकि, इस बात पर ज़ोर देने की ज़रूरत नहीं है कि यदि अनुदान कोयला खदान (संरक्षण और सुरक्षा) नियम,1952 के और.49 के तहत सहायता के माध्यम से था, अनुदान सशर्त है, तो उस स्थिति में केंद्र सरकार बाध्य होगी। और. 54 की आवश्यकताओं का अनुपालन करें और इसे उन उद्देश्यों के लिए लागू करें जिनके लिए इसे प्रदान किया गया था, जैसे भंडारण या अन्य सुरक्षा संचालन और कोयला खदानों के संरक्षण के लिए।

बार्कलेज़ बैंक लिमिटेड बनाम क्विस्ट क्लोज़ इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड 1970 एस सी 567 और कोल प्रोडक्ट्स प्राइवेट **लिमिटेड** बनाम औई टी आ

(1972) 85 और्ट टी और 347 के निर्णयों पर विचार किया , जो दोनों अलग-अलग हैं।

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार:- सिविलअपील संख्या 815,1284/1978

दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा सिविल रिट संख्या - 616/1976 में दिनांक 20-12-1977 को पारित निर्णय एवं आदेश के विरूद्ध विशेष अनुमति याचिका के साथ प्रस्तुत अपीलें ।उपस्थित अपील संख्या 815/78 में अपीलार्थी की और से - सोली जे सोराब जी, ए सी गुलाटी, ए.के. गांगुली, जी.एस. चटर्जी एवं बी.बी. साहनी

अपील संख्या-1284/78 में अपीलार्थी तथा अपील संख्या 815/78 के प्रत्यर्थी संख्या 1 की और से- लाल नारायण सिन्हा, अर्टनी जनरल, सुश्री ए सुभाषनी एवं गिरीश चन्द्र,

न्यायालय द्वारा निर्णय पारित किया गया ।

न्यायाधिपति श्री सैन दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ विशेष अनुमति द्वारा ये अपीले कोकिंग कोल माईन्स (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम के कुछ प्रावधानों के निर्माण पर आधारित है।

अपीलों में यह सवाल उठाया गया है कि क्या कोयला खदान का ठेकेदार उप-एस के तहत मालिक है।(1) कोकिंग कोल माइंस (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1972 (इसके बाद राष्ट्रीयकरण अधिनियम के रूप में संदर्भित)

की धारा 4 का; और यदि हां, तो क्या ऐसे ठेकेदार द्वारा स्थापित या लाई गई मशीनरी, संयंत्र, उपकरण और अन्य संपत्तियों जैसी अचल संपत्तियां केंद्र सरकार में निहित हैं। वे एक सहायक प्रश्न को भी जन्म देते हैं, अर्थात्, क्या कोयला खान (संरक्षण, सुरक्षा और विकास) अधिनियम, 1952 की धारा 4 के तहत स्थापित पूर्ववर्ती कोयला बोर्ड से निर्दिष्ट तिथि तक सब्सिडी, संरक्षण नामक निधि से प्राप्त की जा सकती है। और सुरक्षा निधि, नियत दिन से पहले ऐसे जुटाने वाले ठेकेदार द्वारा, उप-धारा के तहत उनकी शक्तियों के आधार पर केंद्र सरकार द्वारा प्राप्त की जा सकती है। (3) राष्ट्रीयकरण अधिनियम की धारा 22, ऐसे ठेकेदार सहित अन्य सभी व्यक्तियों को बाहर करने के लिए और उप-धाराओं के तहत लागू किया गया। (4) धारा 22 कोकिंग कोयला खदान की देनदारियों के निर्वहन के लिए, जिसे नियत दिन तक चुकाया नहीं जा सका।

बिन्दुओं को बोधगम्य बनाने के लिए कुछ तथ्य बताना आवश्यक है। **मेसर्स बलिहारी कोलियरी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड** के बीच 7 फरवरी, 1969 को हुए एक समझौते के द्वारा । **लिमिटेड** (बाद में मालिक के रूप में संदर्भित) एक हिस्से का और मेसर्स **इंडस्ट्रियल सप्लाइज प्राइवेट लिमिटेड** । **लिमिटेड** (इसके बाद याचिकाकर्ताओं के रूप में संदर्भित) दूसरे भाग का पाठ इस प्रकार किया गया।

"जबकि मालिक एक कामकाजी कोलियरी के मालिक हैं, जिसका क्षेत्रफल कमोबेश 300 बीघे है और जिसे बलिहारी कोलियरी के नाम से जाना जाता है, विशेष रूप से यहां उल्लिखित लीज और उप-पट्टों के तहत लिखित पहली अनुसूची में वर्णित है और उसके संबंध में विभिन्न संरचनाओं, धेवर्शो कुली लाइनों (बाद में उक्त इमारतों के रूप में संदर्भित) का निर्माण किया है और उनमें विभिन्न मशीनरी, संयंत्र उपकरण, उपकरण और बर्तन (बाद में उक्त मशीनरी के रूप में संदर्भित) भी स्थापित और स्थापित किए हैं; और जबकि मालिकों ने **इंडस्ट्रियल सप्लाईज़** प्राइवेट लिमिटेड को अपनी उक्त कोलियरी के प्रबंध ठेकेदार के रूप में नियुक्त किया है और उक्त प्रबंध ठेकेदार इस अवधि के लिए और इसमें शामिल नियमों और शर्तों पर ऐसे प्रबंध ठेकेदार के रूप में कार्य करने के लिए सहमत हो गया है:"

उक्त समझौते के तहत, याचिकाकर्ताओं को 20 साल की अवधि के लिए कच्छी बलिहारी कोलियरी के प्रबंध ठेकेदार के रूप में नियुक्त किया गया था। सीएल के तहत. 7 (ए) याचिकाकर्ताओं को अपनी लागत पर उपकरण, मशीनरी और संयंत्र जैसी अचल संपत्ति स्थापित करने और उक्त कोलियरी में स्टोर जैसी मौजूदा संपत्ति के रूप में निवेश करने और ठेकेदारों को बढ़ाने के समान काम करने की आवश्यकता थी। सीएल द्वारा. 7 (बी) इस प्रकार स्थापित की गई अतिरिक्त मशीनरी और याचिकाकर्ताओं द्वारा लाए गए सामान और बर्तन पूरी तरह से याचिकाकर्ताओं की संपत्ति बने रहेंगे

और समझौते के निर्धारण पर वे सीएल के प्रावधानों के अधीन हकदार थे। 9, ऐसी अतिरिक्त अचल संपत्तियों और चालू संपत्तियों को हटाने के लिए। खंड 9 ने मालिकों को सीएल में उल्लिखित अतिरिक्त मशीनरी, संपत्ति और बर्तन खरीदने का विकल्प दिया। 7. समझौते का खंड 25 हमारे उद्देश्यों के लिए महत्वपूर्ण है और इसमें लिखा है:

> "यदि उक्त कोलियरी का राष्ट्रीयकरण हो जाता है तो ये उपहार निर्धारित किए जाएंगे और इसके प्रावधानों के तहत मालिकों द्वारा प्रबंध ठेकेदार को या प्रबंध ठेकेदार द्वारा मालिकों को देय सभी धनराशि तुरंत देय हो जाएगी और देय होगी जैसा भी मामला हो, मालिक प्रबंध ठेकेदार को या प्रबंध ठेकेदार द्वारा मालिकों को। यदि इस तरह के राष्ट्रीयकरण के परिणामस्वरूप मशीनरी, संपत्ति और बर्तन प्रावधानों के तहत प्रबंध ठेकेदार द्वारा उक्त कोलियरी में स्थापित और/या लाए गए हैं इन उपहारों के खंड 7 या उनमें से किसी एक या अधिक या इन उपहारों के खंड 8 के प्रावधानों के तहत उक्त कोलियरी में इसके द्वारा बनाई गई इमारतों और संरचनाओं को संबंधित अधिकारियों द्वारा ले लिया जाता है और ऐसी स्थिति में प्रबंध ठेकेदार होगा उक्त मशीनरी, संपत्ति और बर्तनों और कब्जे में ली गई इमारतों

और संरचनाओं के लिए देय या उनके कारण होने वाले मुआवजे के हकदार होंगे और मालिक उक्त कोलियरी में शामिल अन्य सभी संपत्तियों के लिए मुआवजा प्राप्त करने के हकदार होंगे।"

उक्त समझौते के तहत, याचिकाकर्ताओं ने समय-समय पर विभिन्न अचल संपत्तियां जैसे मशीनरी, संयंत्र और उपकरण स्थापित किए और संरचनाएं खड़ी कीं और उक्त कोलियरी के भीतर नई सड़कें बनाईं और उक्त के कुशल कामकाज के लिए विभिन्न मौजूदा संपत्ति और चल संपत्तियां लाईं। मेरा याचिकाकर्ता मेसर्स खास धर्मबंद कोलियरी के स्वामित्व वाली खास धर्मबंद कोलियरी के नाम से जानी जाने वाली एक अन्य कोकिंग कोयला खदान के संबंध में भी ठेकेदार जुटा रहे थे। कंपनी **प्रा . लिमिटेड** , जिसे बाद में न्यू धर्मबंद कोलियरी के नाम से जाना गया। उन्होंने इसी तरह स्टोर सहित विभिन्न संपत्तियों को अपने कब्जे में ले लिया था, जिनका उपयोग उक्त कोलियरी में किया जा रहा था। अक्टूबर 1969 के एक समझौते के तहत, न्यू धर्मबंद कोलियरी को मेसर्स सेठिया माइनिंग एंड एमएफजी कॉर्पोरेशन **लिमिटेड** द्वारा खरीद लिया गया था । याचिकाकर्ताओं से संबंधित संयंत्रों, मशीनरी और स्टोर जैसी संपत्तियों की एक सूची तैयार की गई थी जो कोलियरी में पड़ी थीं, जिसका मूल्य लगभग रु 1,21,000/-.

17 अक्टूबर, 1971 को राष्ट्रपति ने 214 कोकिंग कोयला खदानों और 12 कोक ओवन संयंत्रों के प्रबंधन को जनहित में केंद्र सरकार द्वारा अपने अधिकार में लेने का प्रावधान करने के लिए कोकिंग कोयला खदान (आपातकालीन प्रावधान) अध्यादेश 1971 प्रख्यापित किया।, जिसमें विचाराधीन कोयला खदानें भी शामिल हैं, ऐसी खदानों का राष्ट्रीयकरण लंबित है। अध्यादेश को कोकिंग कोल माइंस (आपातकालीन प्रावधान) अधिनियम, 1971 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था। इसके बाद, संसद ने कोकिंग कोयला खानों और कोक ओवन संयंत्रों के राष्ट्रीयकरण की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए कोकिंग कोल माइंस (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1972 लागू किया। यह पहली अनुसूची में निर्दिष्ट कोकिंग कोयला खदानों के मालिकों के अधिकार, स्वामित्व और हित के अधिग्रहण और हस्तांतरण और ऐसे कोक ओवन संयंत्रों के मालिकों के अधिकार, शीर्षक और हित के अधिग्रहण और हस्तांतरण के लिए एक अधिनियम के रूप में हकदार था। लौह और इस्पात उद्योग की बढ़ती आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आवश्यक कोकिंग कोयले के संसाधनों की सुरक्षा, संरक्षण और वैज्ञानिक विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ऐसी खानों और संयंत्रों को पुनर्गठित और पुनर्निर्मित करने की दृष्टि से उक्त कोकिंग कोयला खदानों में या उसके आसपास उससे जुड़े या उसके आनुषंगिक मामले।

"कोकिंग कोल माइंस (आपातकालीन प्रावधान) अधिनियम, 1971 की धारा 2 (ए) के तहत "नियत दिन" 17 अक्टूबर, 1971 था, जबकि कोकिंग कोल माइंस (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम की धारा 3 (ए) के तहत, 1972 1 मई 1972 है।

याचिकाकर्ताओं के अनुसार, 17 अक्टूबर, 1971 को केंद्र सरकार द्वारा अधिग्रहित कच्छी बलिहारी कोलियरी की चल और अचल संपत्ति का कुल मूल्य रु 11,85,591.00. न्यू धरमबंद कोलियरी के संबंध में उनका आरोप है कि अक्टूबर 1969 से 17 अक्टूबर 1971 के बीच मेसर्स सेठिया माइनिंग एंड एमएफजी कॉर्पोरेशन **लिमिटेड** । कोलियरी में पड़े कुछ भंडारों का उपयोग 50,000.00 रुपये की सीमा तक किया था और 17 अक्टूबर, 1971 को कोलियरी में पड़े भंडारों का शेष लगभग रु. 72,000.00. अप्रैल 1969 से जब याचिकाकर्ता कच्छी बलिहारी कोलियरी के ठेकेदार बन गए और 17 अक्टूबर, 1971 तक जब उक्त कोलियरी का प्रबंधन केंद्र सरकार ने अपने हाथ में ले लिया, याचिकाकर्ताओं का आरोप है कि उन्होंने अपनी लागत पर संचालन किया था। रेत भंडारण और हार्डमाइनिंग और तदनुसार समय-समय पर मालिकों के माध्यम से सब्सिडी के लिए कोयला खान (संरक्षण और सुरक्षा) अधिनियम, 1952 की धारा 4 के तहत स्थापित कोयला बोर्ड को बिल जमा किए थे। 17 अक्टूबर, 1971 को उन्हें देय सब्सिडी की राशि लगभग रु. 4,50,000.

5 मई, 1975 को याचिकाकर्ताओं ने दिल्ली उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका दायर कर यह घोषणा करने की मांग की कि उप-एस. धारा 4 का (1) याचिकाकर्ताओं के अधिकार, शीर्षक और हित के अधिग्रहण का प्रावधान नहीं करता है, क्योंकि ठेकेदारों को पालने के कारण वे राष्ट्रीयकरण अधिनियम की धारा 3 (एन) के अर्थ के तहत मालिक नहीं थे और इसलिए, वे दो खदानों में स्थापित मशीनरी, संयंत्र और उपकरण जैसी अचल संपत्तियों को नष्ट करने और हटाने के हकदार थे और साथ ही फर्नीचर, स्टोर आदि जैसी चल और वर्तमान संपत्तियों को हटाने के भी हकदार थे और आगे सब्सिडी की राशि वसूलने के भी हकदार थे। रु. तत्कालीन कोयला बोर्ड से केंद्र सरकार द्वारा 4,50,000/- रुपये एकत्र किये गये। तदनुसार, उन्होंने परमादेश की प्रकृति में एक रिट या निर्देश की मांग की, जिसमें केंद्र सरकार को मशीनरी, संयंत्र, उपकरण और अन्य संपत्ति और चल-अचल संपत्ति और सब्सिडी या अन्य बकाया राशि के माध्यम से एकत्र की गई सभी राशि वापस करने या किसी भी स्थिति में रुपये का भुगतान करने की आवश्यकता हो। 1 मई 1972 से भुगतान की तिथि तक ब्याज सहित 16,35,591/- रु.

उच्च न्यायालय ने याचिकाकर्ताओं के दावे को काफी हद तक अस्वीकार कर दिया, यह मानते हुए कि वे खान अधिनियम, 1952 की धारा 2 (1) के साथ पढ़े गए राष्ट्रीयकरण अधिनियम की धारा 3 (ए) में

परिभाषित मालिक शब्द के अर्थ में आते हैं। और इस तरह दो कोयला खदानों में पड़ी विभिन्न मशीनरी, संयंत्र, उपकरण और अन्य अचल संपत्ति, वर्तमान संपत्ति और चल संपत्ति को राष्ट्रीयकरण के एस 3 (जे) में परिभाषित "खदान" अभिव्यक्ति में शामिल किया गया था। अधिनियम, और इसलिए, उसमें याचिकाकर्ताओं का अधिकार, शीर्षक और हित उप-धाराओं के तहत केंद्र सरकार में निहित थे। (1) धारा 4 सभी दायित्वों से मुक्त। हालाँकि, यह माना गया कि सब्सिडी की राशि रु याचिकाकर्ताओं द्वारा किए गए रेत भंडारण और कठिन खनन कार्यों की लागत की प्रतिपूर्ति के रूप में कोयला बोर्ड से प्राप्त होने वाली 4,50,000/- को उप-धारा के अंतर्गत "कोकिंग कोयला खदान के कारण राशि" के रूप में नहीं माना जा सकता है।. (3) धारा 22 और, इसलिए, उप-एस के तहत केंद्र सरकार द्वारा उपयोग नहीं किया जा सका। (4) कोकिंग कोयला खदान की देनदारियों के निर्वहन के लिए एस 22 याचिकाकर्ताओं द्वारा यह तर्क दिया गया कि वे संबंधित कोयला खदानों के न तो मालिक थे, न ही तत्काल कब्जे वाले या प्रबंध ठेकेदार थे, बल्कि केवल उसके ठेकेदारों को पाल रहे थे और इसलिए, वे मालिक शब्द के दायरे में नहीं आते थे जैसा कि परिभाषित किया गया है। राष्ट्रीयकरण अधिनियम की धारा 3 (एन) को खान अधिनियम, 1952 की धारा 2 (1) के साथ पढ़ा जाता है। इसलिए, यह कहा गया था कि संयंत्र, उपकरण और मशीनरी और अन्य संपत्तियां, और वर्तमान संपत्ति और उनसे संबंधित चल संपत्तियां 17 अक्टूबर, 1971 को उप-धाराओं के तहत

केंद्र सरकार में निहित नहीं किया जा सकता था और न ही किया जा सकता था। (1) राष्ट्रीयकरण अधिनियम की धारा 4। यह आग्रह किया गया था कि उच्च न्यायालय ने खान अधिनियम, 1952 की धारा 2 (1) में परिभाषित मालिक शब्द की परिभाषा को समझने में गलती की है, ताकि एक ठेकेदार को शामिल किया जा सके, शब्दों पर जोर देकर जैसे कि वह परिभाषा के अंतिम वाक्य में थे, और विशेष रूप से इसलिए, क्योंकि अधिनियम स्वयं, एक मालिक और एक ठेकेदार के बीच अलग से और/या स्पष्ट रूप से अंतर करता है। आगे यह तर्क दिया गया कि खान अधिनियम की धारा 2(1) में मालिक की परिभाषा में अंतिम वाक्य में शामिल शब्द की अनुपस्थिति के कारण, एक ठेकेदार को मालिक नहीं माना जा सकता है। यह कहा गया था कि खान अधिनियम, 1952 की धारा 2 (1) में कल्पना का उद्देश्य ऐसे ठेकेदार को उस अधिनियम के प्रावधानों के उचित पालन के लिए जिम्मेदार बनाने के सीमित उद्देश्य के लिए था और इस तरह के प्रावधान को गलत ठहराया जा सकता है। राष्ट्रीयकरण अधिनियम के उद्देश्य और वस्तु को समझने के लिए लागू नहीं किया जाएगा जो अलग-अलग थे, यानी, उप-धाराओं के तहत खदान के भीतर पड़े ऐसे ठेकेदार से संबंधित मशीनरी, संयंत्र और उपकरण और अन्य संपत्तियों को प्राप्त करने के उद्देश्य से (1) अधिनियम की धारा 4। हमें डर है, हम इन विवादों को स्वीकार नहीं कर सकते.

जिस निर्माण को राष्ट्रीयकरण अधिनियम की धारा 3 (एन) में मालिक की परिभाषा पर रखने की मांग की गई है, उसे खान अधिनियम की धारा 2 (1) के साथ पढ़ा जाए, जिसके आधार पर तर्क आगे बढ़ता है, यदि स्वीकार कर लिया, कानून के मूल उद्देश्य को ही विफल कर दिया।राष्ट्रीयकरण अधिनियम उप-धाराओं द्वारा प्रदान करता है। धारा 4 के (1) कि पहली अनुसूची में निर्दिष्ट कोकिंग कोयला खदानों के संबंध में मालिकों के अधिकार, स्वामित्व और हित, नियत दिन पर, यानी 17 अक्टूबर, 1971 को सभी को हस्तांतरित हो जाएंगे, पूरी तरह से निहित हो जाएंगे केंद्र सरकार में सभी दायित्वों से मुक्त।

राष्ट्रीयकरण अधिनियम में, मालिक को धारा 3 (एन) में इस प्रकार परिभाषित किया गया है: "3 (एन) "मालिक", -

(i) जब किसी खान के संबंध में उपयोग किया जाता है, तो उसका वही अर्थ होता है जो खान अधिनियम, 1952 में दिया गया है;

(ii) जब कोक ओवन प्लांट के संबंध में उपयोग किया जाता है, तो इसका मतलब है कोई भी व्यक्ति जो कोक ओवन प्लांट या उसके किसी हिस्से का तत्काल मालिक या पट्टेदार या अधिभोगी है या कोक ओवन प्लांट या उसके किसी हिस्से के काम के लिए ठेकेदार है"

खान अधिनियम, 1952 की धारा 2(1) इस प्रकार है:

"(1) "मालिक", जब किसी खदान के संबंध में उपयोग किया जाता है, तो इसका मतलब कोई भी व्यक्ति होता है जो खदान या उसके किसी भी हिस्से का तत्काल मालिक या पट्टेदार या अधिभोगी होता है और खदान के मामले में व्यवसाय चल रहा होता है किसी परिसमापक या रिसीवर द्वारा, ऐसे परिसमापक या रिसीवर द्वारा और किसी कंपनी के स्वामित्व वाली खदान के मामले में, जिसका व्यवसाय एक प्रबंध एजेंट द्वारा किया जा रहा है, ऐसे प्रबंध एजेंट; लेकिन इसमें वह व्यक्ति शामिल नहीं है जो केवल रॉयल्टी, किराया प्राप्त करता है या खदान से जुर्माना या केवल खदान का मालिक है, जो उसके कामकाज के लिए किसी पट्टे, अनुदान या लाइसेंस के अधीन है या केवल तेल का मालिक है और खदान के खनिजों में रुचि नहीं रखता है; लेकिन काम करने के लिए कोई ठेकेदार है किसी खदान या उसके किसी भी हिस्से पर इस अधिनियम के तहत उसी तरह से अधीन किया जाएगा जैसे कि वह एक मालिक था, लेकिन ऐसा नहीं कि मालिक को किसी भी दायित्व से छूट मिल जाए;"

इस तर्क के समर्थन में कि याचिकाकर्ताओं को कब्जाधारी नहीं माना जा सकता है और इसलिए, वे राष्ट्रीयकरण अधिनियम की धारा 3 (एन) के तहत मालिक की परिभाषा में नहीं आते हैं, मुख्य निरीक्षक के फैसले पर भरोसा किया गया था ऑफ माइंस बनाम करमचंद थापर, (1962) 1 एस सी और 9 । हालाँकि, एक उठान अनुबंध एक पट्टा नहीं हो सकता है और इसलिए, ठेकेदार एक पट्टेदार नहीं है, हमें कोई कारण नहीं मिलता है कि उसे एस 3 (एन) के अर्थ के तहत एक अधिभोगी क्यों नहीं माना जाना चाहिए। 7 फरवरी, 1969 के समझौते की शर्तों के तहत, याचिकाकर्ताओं ने 20 वर्षों की अवधि के लिए कोलियरी पर पूर्ण प्रभुत्व और नियंत्रण हासिल कर लिया। यह सामान्य आधार है कि उक्त समझौता एक पंजीकृत दस्तावेज़ द्वारा किया गया था और भले ही यह शायद पट्टे के बराबर न हो, इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता है कि यह अनुदान के साथ एक लाइसेंस था। याचिकाकर्ता सीएल के आधार पर थे। समझौते के 7 (ए) में कोयले के परिवहन के संबंध में अपनी लागत पर ऐसी अतिरिक्त मशीनरी, ट्रामवे, रोपवे आदि स्थापित करने और कोयले की खोज और हटाने के उद्देश्य से संपत्तियां लाने का अधिकार है। वह सीएल के तहत हकदार थे। 7 (बी) ऐसी अतिरिक्त मशीनरी को हटाने के लिए जो स्थापित की जा सकती है और ऐसे सामान और बर्तन जो उनके द्वारा उक्त कोलियरियों में लाए जा सकते हैं, जब तक कि निश्चित रूप से, मालिकों ने सीएल के तहत इसे खरीदने के अपने विकल्प का प्रयोग नहीं किया हो। 9. इन शर्तों के

मद्देनजर यह तर्क देना व्यर्थ है कि याचिकाकर्ता खदानों के कब्जेदार नहीं थे। प्रश्नगत कोयला खदान का वास्तविक उपयोग और कब्ज़ा उनके पास था। हमने करमचंद थापर मामले में फैसले को ध्यानपूर्वक पढ़ा है ए औई और 1961 एससी पेज 836 और, यदि हम ऐसा कह सकते हैं, तो निर्णय तथ्यों पर भिन्न है। वहां सवाल यह था कि क्या कोलियरी का मालिकाना हक रखने वाली कंपनी का प्रबंध एजेंट कोलियरी का अधिभोगी था और न्यायालय ने यह कहते हुए इसे खारिज कर दिया:

> "खदान के तत्काल मालिक, या पट्टेदार या कब्जेदार" शब्दों के संयोजन से, यह स्पष्ट रूप से स्पष्ट है कि केवल एक व्यक्ति जिसका व्यवसाय एक ही चरित्र का है, यानी, मालिक या पट्टेदार द्वारा कब्जे के माध्यम से कब्जा परिभाषा में "कब्जाधारी" शब्द का अर्थ उसकी ओर से है न कि किसी और की ओर से। इस प्रकार, सही मालिक को छोड़कर गलत तरीके से कब्ज़ा करने वाला एक अतिचारी खदान का कब्ज़ाकर्ता होगा, और इसलिए अधिनियम के प्रयोजन के लिए मालिक होगा।

न्यायालय ने आगे कहा:

> "ऐसा इसलिए होना चाहिए क्योंकि किसी और की ओर से कब्ज़ा करना विधायिका के विचार में ऐसा "कब्जा" नहीं

था, जिससे कि कब्जे वाले व्यक्ति को धारा 2 (1) के अर्थ में "कब्जाधारी" बना दिया जाए।"

ये टिप्पणियाँ, यदि हम ऐसा कह सकें, बड़े सम्मान के साथ, बल्कि व्यापक रूप से कही गई हैं। वे वास्तव में इस बात के प्रति संवेदनशील हैं कि किसी खदान के मालिक या पट्टेदार की ओर से कब्जे में रहने वाला ठेकेदार राष्ट्रीयकरण अधिनियम की धारा 2 के साथ पढ़े जाने वाली धारा 3 (एन) के अर्थ के तहत कब्जाधारी नहीं है। 1) खान अधिनियम, 1952 का। हमें पूरा यकीन है कि विधायिका का इरादा ऐसा नहीं था। ऐसा कोई कारण नहीं है कि अधिभोगी शब्द को उसके सामान्य अर्थ के अनुसार उसके सामान्य अर्थ में प्रयुक्त न समझा जाए। आम बोलचाल में, कब्ज़ा करने वाला वह होता है जो कब्ज़ा कर लेता है या (आमतौर पर) कब्ज़ा रखता है: शॉर्टर ऑक्सफ़ोर्ड डिक्शनरी, तीसरा संस्करण, वॉल्यूम। 2. पी. 1433. कानूनी अर्थ में, कब्ज़ाकर्ता वास्तविक कब्ज़ा करने वाला व्यक्ति होता है। ठेकेदारों को खड़ा करने वाले याचिकाकर्ता, 7 फरवरी 1969 के समझौते की शर्तों के तहत, कोलियरी के वास्तविक भौतिक कब्जे और आनंद के हकदार थे, और इसलिए, उसके कब्जे वाले थे। ऐसा होने पर, समझौते के तहत उनके द्वारा प्राप्त किए गए पर्याप्त अधिकारों के आधार पर, याचिकाकर्ताओं का कब्ज़ा अपने अधिकार में था, किसी और की ओर से कब्ज़ा नहीं था

और इसलिए, करमचंद थापर्स मामले में निर्णय (ए औई और 1961 एस सी पेज 838) आवेदन नहीं कर सकते।

यह आग्रह किया जाता है कि राष्ट्रीयकरण अधिनियम स्वयं एक मालिक और एक प्रबंध ठेकेदार के बीच अंतर करता है, दोनों के संबंध में अलग-अलग प्रावधान किए गए हैं। कहा जा रहा है कि इसे देखते हुए उपधारा में मालिक शब्द के स्थान पर ठेकेदार शब्द पढ़ने का कोई कानूनी औचित्य नहीं है। (1) धारा का 4. विवाद पूरी तरह से गलत है और इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि राष्ट्रीयकरण अधिनियम मालिक और प्रबंध ठेकेदार को अलग-अलग परिभाषित करता है। धारा 3 (i) में प्रबंध ठेकेदार की परिभाषा इस प्रकार है:

> "3 (i) प्रबंध ठेकेदार" का अर्थ है वह व्यक्ति, या व्यक्तियों का समूह, जिसने राज्य सरकार की लिखित पूर्व सहमति से कोकिंग कोयला खदान या कोक ओवन संयंत्र के मालिक के साथ एक व्यवस्था, अनुबंध या समझौता किया है। जिसके तहत कोकिंग कोयला खदान या कोक ओवन संयंत्र का संचालन ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों के निकाय द्वारा काफी हद तक नियंत्रित किया जाता है;"

अधिनियम में प्रयुक्त और परिभाषित शब्दों और अभिव्यक्तियों का क्रमशः वही अर्थ है जो उन्हें दिया गया है, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा

अपेक्षित न हो। अभिव्यक्ति प्रबंध ठेकेदार को अध्याय VI में जगह मिलती है, जो उप-धाराओं के तहत नियुक्त भुगतान आयुक्त की शक्ति, कार्यों और कर्तव्यों से संबंधित है। (1) एस. 20, प्रत्येक कोकिंग कोयला खदान या कोक ओवन संयंत्र के मालिक को देय राशि के वितरण के उद्देश्य से। यह उप-एस में दिखाई देता है. (2) एस 26 का, जो प्रदान करता है:

> "(2) एक कोकिंग कोयला खदान या कोक ओवन संयंत्र के संबंध में, जिसका संचालन 17 अक्टूबर, 1971 से ठीक पहले एक प्रबंध ठेकेदार के नियंत्रण में था, ऐसे कोकिंग कोयले के खिलाफ पहली अनुसूची में निर्दिष्ट राशि खदान या ऐसे कोक ओवन संयंत्र के खिलाफ दूसरी अनुसूची में कोकिंग कोयला खदान या कोक ओवन संयंत्र के मालिक और ऐसे प्रबंध ठेकेदार के बीच ऐसे अनुपात में विभाजित किया जाएगा जिस पर मालिक और ऐसे प्रबंध ठेकेदार के बीच सहमति हो सकती है, और ऐसा कोई समझौता न होने की स्थिति में, ऐसे अनुपात में, जैसा न्यायालय द्वारा निर्धारित किया जा सकता है।"

22. सीएल के तहत. समझौते के 25 में, पार्टियों के बीच इस बात पर सहमति हुई कि (i) कोलियरी का राष्ट्रीयकरण होने की स्थिति में, समझौता निर्धारित किया जाएगा और मालिकों द्वारा याचिकाकर्ताओं को देय

और इसके विपरीत सभी पैसे तुरंत देय हो जाएंगे और देय, और (ii) ऐसे राष्ट्रीयकरण की स्थिति में, यदि याचिकाकर्ताओं द्वारा कोलियरी में स्थापित और/या लाई गई मशीनरी, संपत्ति और बर्तन या उनके द्वारा बनाई गई इमारतों और संरचनाओं को अधिकारियों द्वारा ले लिया जाता है, तो वे उक्त मशीनरी, संपत्ति और बर्तनों और इस प्रकार अधिग्रहीत की गई इमारतों और संरचनाओं के लिए देय या उनके कारण होने वाले मुआवजे के हकदार हो जाएंगे और मालिक उक्त कोलियरी में शामिल अन्य सभी संपत्तियों के लिए मुआवजा प्राप्त करने के हकदार होंगे। राष्ट्रीयकरण अधिनियम की धारा 3 (i) में परिभाषित अभिव्यक्ति प्रबंध ठेकेदार की अभिव्यक्ति केवल उप-धाराओं के तहत मुआवजे के बंटवारे के उद्देश्य से आती है। (2) धारा 26 का। प्रस्तुतीकरण कि उपधारा में स्वामी शब्द का प्रयोग किया गया है। (1) राष्ट्रीयकरण अधिनियम की धारा 4 में एक प्रबंध ठेकेदार को शामिल नहीं किया गया है जो अधिनियम की योजना के विरुद्ध है। उप-एस में मालिक शब्द। अधिनियम की धारा 4 के (1) का अर्थ धारा 3 (एन) में निहित परिभाषा में दिया गया अर्थ होना चाहिए।

यह दावा किया गया कि याचिकाकर्ता वास्तव में प्रबंध ठेकेदार नहीं थे, लेकिन समझौते में उन्हें गलत तरीके से वर्णित किया गया था। हालाँकि, समझौते का मात्र अवलोकन, तर्क को नष्ट करने वाला होगा। यह एक दस्तावेज़ है जिसमें पार्टियों के पारस्परिक अधिकारों और दायित्वों को

परिभाषित करने वाले 46 खंड शामिल हैं। याचिकाकर्ताओं को जीतने, अनड्रेसिंग कोयला प्राप्त करने के लिए खदान में काम करने के सभी अधिकार प्रदान किए गए। उन्हें देय तथाकथित पारिश्रमिक वस्तुतः आपूर्ति किए गए कोयले की कीमत थी जिससे मालिकों को लाभ का एक मार्जिन मिलता था। यहां तक कि खदान के संबंध में किराया रॉयल्टी, कर आदि के भुगतान का दायित्व भी याचिकाकर्ताओं पर डाला गया था। इन शर्तों के मद्देनजर, उन्हें यह कहते हुए नहीं सुना जा सकता कि वे प्रबंध ठेकेदार नहीं थे, हालांकि समझौते की प्रस्तावना और उसके प्रत्येक खंड में उनका ऐसा वर्णन किया गया है। हालाँकि, यह दावा किया गया है कि एक प्रबंध ठेकेदार के कार्य, अर्थात् प्रबंधकों की नियुक्ति, याचिकाकर्ताओं को नहीं सौंपी गई थी, बल्कि वास्तव में एक अलग समझौते के तहत मेसर्स मधुसूदन एंड कंपनी को सौंपी गई थी। सबमिशन सीएल की शर्तों से लिखा गया है। 11 कोलियरी के श्रमिकों के नियोजन से संबंधित। जो कुछ किया गया वह यह था कि पूर्ववर्ती मालिकों ने इस खंड के द्वारा प्रबंधकों को नियुक्त करने की शक्ति अपने पास औरक्षित कर ली थी। इस तरह का औरक्षण याचिकाकर्ताओं को राष्ट्रीयकरण अधिनियम की धारा 3(i) के तहत प्रबंध ठेकेदार की परिभाषा से बाहर नहीं करता है, क्योंकि उनके पास अभी भी खदान पर पर्याप्त नियंत्रण था। यह दलील कि वे नहीं बल्कि कोई और प्रबंध ठेकेदार था, केवल एक बाद का विचार है। याचिकाकर्ताओं को समझौते की शर्तों से बंधे होने के कारण उप-धाराओं के प्रावधानों से बचने

की अनुमति नहीं दी जा सकती। (1) धारा 4 में, क्योंकि वे धारा में मालिक की परिभाषा के दायरे में आते हैं। राष्ट्रीयकरण अधिनियम की धारा 3 (एन)।

वैकल्पिक रूप से, यह तर्क दिया जाता है कि खान अधिनियम, 1952 की धारा 2 (1) के साथ पढ़े जाने वाले राष्ट्रीयकरण अधिनियम की धारा 3 (एन) में परिभाषित मालिक शब्द किसी भी स्थिति में शामिल नहीं है। उठाने वाला ठेकेदार. यह सुझाव नहीं दिया गया है कि एक उठाने वाला ठेकेदार एस 2 (1) में एक ठेकेदार के विवरण के अंतर्गत नहीं आता है, लेकिन यह आग्रह किया जाता है कि कार्य में शामिल नहीं है। संसद को शामिल शब्द डालने की कोई आवश्यकता नहीं थी क्योंकि ये शब्द ऐसे थे जैसे कि वह थे। हालाँकि आम बोलचाल की भाषा में मालिक शब्द, अपने सामान्य अर्थ में, एक खदान के स्वामित्व को दर्शाता है, इस शब्द को कानूनी अर्थ में समझा जाना चाहिए, जैसा कि परिभाषित किया गया है।

संसद ने उचित विचार-विमर्श के साथ, राष्ट्रीयकरण अधिनियम को सर्वव्यापी और पूरी तरह से प्रभावी बनाने के लिए खान अधिनियम, 1952 की धारा 2 (1) में मालिक की विस्तृत परिभाषा को शामिल करके धारा 3 (एन) में अपनाया। यह परिभाषा इतनी व्यापक है कि इसमें व्यक्तियों की तीन श्रेणियां शामिल की जा सकती हैं: (i) खदान के संबंध में वह व्यक्ति जो मेरा या उसके किसी हिस्से का तत्काल मालिक या पट्टेदार या

कब्जाधारी है, (ii) खदान के मामले में व्यवसाय जिसका संचालन एक परिसमापक या रिसीवर द्वारा किया जाता है, ऐसे परिसमापक या रिसीवर, और (iii) किसी कंपनी के स्वामित्व वाली खदान के मामले में, जिसका व्यवसाय एक प्रबंध एजेंट, ऐसे प्रबंध एजेंट द्वारा किया जाता है। प्रत्येक व्यक्तियों की एक अलग और अलग श्रेणी है और स्वामित्व की अवधारणा इसमें नहीं आती है। फिर महत्वपूर्ण अंतिम शब्द आते हैं: "लेकिन खदान या उसके किसी भी हिस्से के काम के लिए कोई भी ठेकेदार इस अधिनियम के अधीन होगा जैसे कि यदि वह स्वामी होता, परन्तु इसलिए नहीं कि स्वामी को किसी भी दायित्व से छूट मिल सके।" इस खंड को शामिल करने से मालिक और ठेकेदार दोनों को अधिनियम के उचित पालन के लिए समान रूप से उत्तरदायी बनाया जाता है। इस बात पर ज़ोर देने की ज़रूरत नहीं है कि खान अधिनियम, 1952 में खानों और उनमें कार्यरत व्यक्तियों की सुरक्षा के लिए विभिन्न प्रावधान शामिल हैं। किसी खदान के मामले में, जिसका काम एक ठेकेदार द्वारा किया जा रहा है, वह मुख्य रूप से अधिनियम के प्रावधानों का अनुपालन करने के लिए जिम्मेदार है। यद्यपि किसी खदान या उसके किसी हिस्से के काम के लिए ठेकेदार मालिक नहीं है, वह अधिनियम के प्रावधानों के अधीन होगा, उसी तरह जैसे कि वह मालिक था, लेकिन मालिक को किसी भी दायित्व से मुक्त नहीं किया जाएगा।.

अब यह स्वयंसिद्ध है कि जब किसी कानूनी कल्पना को किसी क़ानून में शामिल किया जाता है, तो न्यायालय को यह सुनिश्चित करना होगा कि कल्पना किस उद्देश्य से बनाई गई है। उद्देश्य सुनिश्चित करने के बाद वैधानिक कल्पना पर पूरा प्रभाव डालना चाहिए और उसे तार्किक परिणति तक ले जाना चाहिए। न्यायालय को उन सभी तथ्यों और परिणामों को मानना होगा जो कल्पना को प्रभावी बनाने के लिए आकस्मिक या अपरिहार्य परिणाम हैं। खान अधिनियम की धारा 2 (1) के साथ पढ़े गए राष्ट्रीयकरण अधिनियम की धारा 3 (एन) में मालिक की परिभाषा में "मानो वह थे" शब्दों का कानूनी प्रभाव यह है कि हालांकि याचिकाकर्ता मालिक नहीं थे, खदान के कामकाज के लिए ठेकेदार होने के नाते उनके साथ वैसा ही व्यवहार किया जाना चाहिए था, हालांकि वास्तव में, वे ऐसे नहीं थे। **ईस्ट एंड डवेलिंग कंपनी लिमिटेड** बनाम फिन्सबरी बरो काउंसिल 1952 एसी, 109 पेज 132 एक कानूनी कल्पना के कानूनी प्रभाव को इन शब्दों में सामने लाता है:

> "यदि आपको मामलों की एक काल्पनिक स्थिति को वास्तविक मानने के लिए बाध्य किया जाता है, तो आपको निश्चित रूप से, जब तक कि ऐसा करने से प्रतिबंधित नहीं किया जाता है, वास्तविक परिणाम और घटनाओं की भी कल्पना करनी चाहिए, यदि मामलों की अनुमानित स्थिति

वास्तव में अस्तित्व में थी, तो अनिवार्य रूप से प्रवाहित होना चाहिए इसके साथ या इसके साथ... क़ानून कहता है कि आपको मामलों की एक निश्चित स्थिति की कल्पना करनी चाहिए; यह नहीं कहता है कि ऐसा करने के बाद, जब उस स्थिति के अपरिहार्य परिणामों की बात आती है तो आपको रुक जाना चाहिए या अपनी कल्पना को भटकने देना चाहिए मामलों का।"

राष्ट्रीयकरण अधिनियम का पूरा उद्देश्य और उद्देश्य कोकिंग कोयला खदानों के निजी स्वामित्व और उसमें निर्मित सभी हितों को जब्त करना है। यह उप-एस द्वारा प्रदान करता है। धारा 4 के (1) कि नियत दिन पर, पहली अनुसूची में निर्दिष्ट कोकिंग कोयला खदानों के संबंध में मालिकों के अधिकार, शीर्षक और हित पूरी तरह से केंद्र सरकार को हस्तांतरित हो जाएंगे और उनमें निहित हो जाएंगे। सभी अवलंबन. अब जब तक कि उप-एस में मालिक शब्द न हो। धारा 4 के (1) को एक विस्तारित अर्थ दिया गया है ताकि एक खदान या उसके किसी हिस्से के काम के लिए एक ठेकेदार को शामिल किया जा सके, कानून का उद्देश्य ही विफल हो जाएगा। यह माना जाना चाहिए कि संसद को सभी कोयला खदानों के काम करने के सामान्य पैटर्न, यानी ठेकेदारों को नियुक्त करने के बारे में पूरी जानकारी थी। कोई भी अन्य निर्माण स्पष्ट रूप से बेहूदगी की ओर ले जाएगा और

संसद को ऐसा परिणाम देगा जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। इसके परिणामस्वरूप ठेकेदार उप-धारा के तहत निहित होने के परिणामों से बच जायेंगे। (1) अधिनियम की धारा 4 और उन्हें खानों के काम के लिए उपयोग की जा रही अतिरिक्त मशीनरी, संयंत्रों और उपकरणों को नष्ट करने और हटाने की अनुमति दें।

यह हमें अगले प्रश्न पर लाता है, अर्थात् क्या रुपये की राशि। 4,50,000/- याचिकाकर्ताओं द्वारा पूर्ववर्ती कोयला बोर्ड से प्राप्य, एक ट्रस्ट से प्रभावित राशि थी, जिसे एक विशिष्ट उद्देश्य के लिए उन्नत किया गया था, अर्थात भंडारण और अन्य सुरक्षा संचालन और कोयला खदानों के संरक्षण के लिए, और नहीं किया जा सकता था उप-एस के अंतर्गत "कोकिंग कोयला खदानों के कारण कोई भी धन" के रूप में माना जाता है। (3) अधिनियम की धारा 22 और केंद्र सरकार, इसलिए, सब्सिडी की राशि को विनियोजित नहीं कर सकी और उप-धाराओं के तहत इसका उपयोग नहीं कर सकी। (4) उसके या कोकिंग कोयला खदानों की देनदारियों को पूरा करना।

इस बिंदु पर उच्च न्यायालय का निष्कर्ष निम्नलिखित परिच्छेद में निहित है:

> "सब्सिडी की देय राशि कोकिंग कोयला खदान की वर्तमान संपत्ति नहीं हो सकती है क्योंकि इसका उपयोग एक निश्चित

निर्दिष्ट उद्देश्य के लिए किया जाना था। तत्काल मामले में स्टोविंग और अन्य सुरक्षा कार्यों की लागत पहले ही खर्च की जा चुकी थी और सब्सिडी वैसे ही थी प्रतिपूर्ति की। राशि की पहचान पहले ही याचिकाकर्ता से संबंधित के रूप में की गई थी और यह सादृश्य पर या किसी विशिष्ट उद्देश्य से प्रभावित ट्रस्ट धन की प्रकृति में है।"

उस निष्कर्ष पर पहुंचने में, उसने बार्कलेज़ बैंक लिमिटेड बनाम क्विस्ट क्लोज़ इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड 1970 एस सर 567 और कोल प्रोडक्ट्स प्राइवेट **लिमिटेड** बनाम आई.-टी. ओ, (1972) 85 आईटीऔर 347 के निर्णयों पर विचार किया, जो दोनों अलग-अलग हैं। वे सिद्धांतों का प्रतिपादन करते हैं कि जब संपत्ति विशिष्ट उद्देश्य के लिए सौंपी जाती है, तो इसे एक ट्रस्ट के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। यह कुछ हद तक अतार्किक लगता है कि परिणामी विश्वास के न्यायसंगत सिद्धांत को कोकिंग कोल माइंस (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1972 जैसे राष्ट्रीयकरण से संबंधित कानून के प्रावधानों के निर्माण में लाया जाना चाहिए। बार्कलेज बैंक लिमिटेड **में**। वी.क्विस्टक्लोज़ इन्वेस्टमेंट्स **लिमिटेड** , हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने एक कंपनी के परिसमापन के बाद सेट-ऑफ के अधिकारों के सवाल पर विचार किया। यह सिद्धांत एक विशिष्ट उद्देश्य के लिए किसी कंपनी को उधार दी गई धनराशि (बाद में समाप्त हो गई) पर लागू किया गया था,

अर्थात लाभांश का भुगतान, जिसे लागू नहीं किया गया था; पैसा, अभी भी पहचाने जाने योग्य होने के कारण, एक ट्रस्ट से प्रभावित माना जाता था, और तदनुसार लेनदारों के सामान्य निकाय के लाभ के लिए नहीं था, लेकिन ऋणदाता द्वारा वसूली योग्य था। **कोल प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड** बनाम औई टी ओ में कलकत्ता उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश द्वारा "सहायता" के लिए इस सिद्धांत का विस्तार किया गया था, जो निर्धारिती को देय था और आयकर विभाग द्वारा गार्निशी कार्यवाही के माध्यम से संलग्न करने की मांग की गई थी। आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 226 (3) (i)। कोयला खान (संरक्षण और सुरक्षा) नियम, 1952 के और 49 के तहत सहायता प्रदान करने के लिए एक आवेदन किया गया था। इसके साथ कुछ शर्तें जुड़ी हुई थीं। और. 54 के तहत अनुदान। कलकत्ता उच्च न्यायालय के समक्ष एक हलफनामा दायर किया गया था जिसमें दिखाया गया था कि अनुदान इस शर्त के अधीन था कि इसका उपयोग कोयला खदान में स्टोविंग और अन्य जुड़े कार्यों के लिए किया जाएगा। उच्च न्यायालय ने गार्निशी नोटिस को इस आधार पर रद्द कर दिया कि आयकर विभाग निर्धारिती की आयकर देनदारियों के भुगतान के लिए धन के किसी भी हिस्से का हकदार नहीं था, क्योंकि कोयले का उपयोग केवल भंडारण और अन्य उद्देश्यों के लिए किया जाना था। कोयला खदानों का सुरक्षा संचालन और संरक्षण।

दो प्रश्न उठते हैं, दोनों का उत्तर भारत संघ के पक्ष में दिया जाना चाहिए। पहला यह कि क्या रुपये का भुगतान किया जाएगा। 4,50,000/- रुपये एक विशेष उद्देश्य के लिए दिए गए थे, यानी और. 49 के तहत सहायता के रूप में, न कि प्रतिपूर्ति के रूप में। दूसरा यह है कि क्या, उस स्थिति में, पैसा किसी विशेष उद्देश्य के लिए दिया गया था, और वह एक विशिष्ट ट्रस्ट से इतना जुड़ा हुआ था कि उसे केंद्र सरकार द्वारा उप-धाराओं के तहत समायोजित नहीं किया जा सकता था। (4) कोकिंग कोयला खदानों की देनदारियों के प्रति राष्ट्रीयकरण अधिनियम की धारा 22 यह सटीक रूप से स्थापित करना मुश्किल नहीं है कि तत्कालीन कोयला बोर्ड द्वारा किन शर्तों पर पैसा दिया गया था। याचिकाकर्ताओं की ओर से, यह विवादित नहीं है कि सब्सिडी के बिल भंडारण और संबंधित सुरक्षा कार्यों और कठिन खनन कार्यों की लागत के लिए थे, जिसे याचिकाकर्ताओं ने 17 अक्टूबर, 1971 से पहले ही अपनी लागत पर पूरा कर लिया था। बाहर। यदि ऐसा है, तो अपरिहार्य निष्कर्ष यह है कि प्रश्न में सब्सिडी की राशि नियत दिन से पहले कोकिंग कोयला खदान के कारण किसी अन्य राशि की तरह थी,और इसलिए, धारा 22 की उपधारा 3 के दायरे से बाहर नहीं आती थी।प्रश्नगत भुगतान कोयला खदानों के भंडारण और अन्य सुरक्षा कार्यों और संरक्षण के लिए तत्कालीन कोयला बोर्ड से प्राप्त होने वाली सहायता के माध्यम से नहीं था। वर्तमान मामले में, याचिकाकर्ताओं ने स्वयं यह दिखाते हुए पहले ही रेत भंडारण और कठिन खनन कार्य किए थे और प्रतिपूर्ति के माध्यम से

सब्सिडी के लिए आवेदन किया था। रुपये का भुगतान. इसलिए, 4,50,000/- पहले से किए गए व्यय की प्रतिपूर्ति के लिए था। निस्संदेह, विवादग्रस्त राशि प्रतिपूर्ति के माध्यम से देय थी। इसलिए, याचिकाकर्ता अपनी इच्छानुसार किसी भी तरीके से धन का उपयोग करने के लिए स्वतंत्र थे। दूसरे शब्दों में, अनुदान किसी विशेष उद्देश्य या उद्देश्य से प्रभावित नहीं था।

भले ही पूर्ववर्ती कोयला बोर्ड से प्राप्त होने वाली सब्सिडी सहायता के रूप में थी, रुपये की राशि। 4,50,000/- केंद्र सरकार द्वारा वसूली योग्य थी जिसमें कोकिंग कोयला खदानें उप-धाराओं के तहत निहित हैं। (1) राष्ट्रीयकरण अधिनियम की धारा 4 और याचिकाकर्ताओं द्वारा नहीं। हालाँकि, इस बात पर ज़ोर देने की ज़रूरत नहीं है कि यदि अनुदान कोयला खदान (संरक्षण और सुरक्षा) नियम, 1952 के और.49 के तहत सहायता के माध्यम से था, अनुदान सशर्त है, तो उस स्थिति में केंद्र सरकार बाध्य होगी। और. 54 की आवश्यकताओं का अनुपालन करें और इसे उन उद्देश्यों के लिए लागू करें जिनके लिए इसे प्रदान किया गया था, जैसे भंडारण या अन्य सुरक्षा संचालन और कोयला खदानों के संरक्षण के लिए इन कारणों से, उच्च न्यायालय के फैसले ने रुपये की सब्सिडी राशि के संबंध में याचिकाकर्ताओं के दावे को आंशिक रूप से अनुमति दी। 4,50,000/- को रद्द किया जाता है, और रिट याचिका खारिज कर दी जाती है। तदनुसार,

भारत संघ की अपील स्वीकार की जाती है और **औद्योगिक आपूर्ति प्राइवेट लिमिटेड** की अपील को संपूर्ण लागत सहित खारिज किया जाता है।

अपील खारिज

यह अनुवाद और्टिफिशियल टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी सीताराम मीना, (आर जे एस) द्वारा किया गया। अस्वीकरणः यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानिय भाषा में अनुवादित किया गया है ओर किसी अन्य उददेश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक ओर अधिकारिक उददेश्यों के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा ओर निष्पादन व कार्यान्वयन के उददेश्य से अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।

***